Investment by Israeli company on 100 per cent basis

2069. SHRI YERRA NARAYANA-SWAMY: Willi the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Andhra Pradesh Govern, ment has soug'ht permission for foreign Investnient on 100 per cent basis with an Israeli company named M/s. B.H.C. Company, Israel;

(b) the stage of processing of this application at present;

(c) when will this application be cleared; and

(d) the reasons for delay in granting clearance?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN); (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The approval has already been granted to the company.

Delicesing *of* industries from the purview of the Indusitres (Development and Regulation) Act

2070. DR. ALLADI P. RAJKUMAR; Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have recently decided to delicence certain Industries from the purview of Industries (Development and Regulation) Act and also given sweeping powers to the "Navratna" public sector enterprises;

(b) if so, the details of these proposals; and

(c) the criteria followed while selecting the "Navratna" enterprises and the significance of "Navratna" enterprises?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a; and (b) Yes, Sir. The Government have delicensed, vide Press Note No. 11 (1997 Seriei) dated nth luly, 1997, five indus-triies, namely^ (i) Animal fats and Oils; (ii) Tanned or dressed fur skins, chamois leather; (iii) Asbestos and asbestos-base products; (iv) Plywood, veneers of all types and other wood based products such as particle board, medium density fibre board/block board; and (v) Paper and newsprint except bagasse based units.

Navratna enterprises have been granted enhanced financial and managerial autonomy and operational freedom to enable them to become global giants.

(c) The criteria for selecting the enterprises included factors like size, per-formance, future prospects, potential to become global giants, etc. The benefits accruing to these nine enterpri^ies include suibsSantially enhanced financiiaJ powers and greater operational freedom.

Slow, down in the produlcftion of Passenger cars

2071. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that automobile productions especially the passenger cars have came down;

(b) if so, to what extent, details of last thee years; and

(c) the reasons for reductions in pro-ductions?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उत्तर प्रदेश के औद्योगिकरण हेतु सरकार के प्रयास

2072. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या आयोग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **:**

(क) केन्द्र सरकार राज्य के विशेषकर उद्योग रहित जिलों और ब्लाकों के औद्यौगिकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे हैं प्रयासों का किस प्रकार समर्थन और उनकी सम्पूर्ति कर रही है, तत्संबंध ब्यौरा क्या है **;**

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य के लिए धनराशि विनिर्दिष्ट की गई है, और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क)से (ग) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकरण के लिए तीन योजनांए चलाता हैं । ये योजनांए उत्तर प्रदेश राज्य पर भी लागू होती है । ये निम्नलिखित है :-

1. **विकास केन्द्र योजना :** इस योजना के अंतर्गत 400-800 हेक्टेयर क्षेत्र में मूलभूत औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास जैसे विद्युत,जल,दूर संचार आदि के विकास सहित विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है । विकास केन्द्र के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति को देखते हुए 10 करोड़ रूपये तक की केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा सकती है । उत्तर प्रदेश राज्य के लिये 8 विकास केन्द्रों का पहले ही अनुमोदन हो गया है तथा 2020 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही रिलीज कर दी गई हैं । ये केन्द्र बचौली बुजुर्ग (झांसी) बंधारा (शाहजहां पुर, चौधरपुर (मुरादाबाद), खुर्जा (बुलन्दशहर), मूंगरा स्थारिया (जौनपुर), शाहजहानंव (गोरखपुर में हैं दिवियापुर (इटावा) तथा पदमपुर-शिवराजपुर (पौडी गढ़वाल), के संबध में राज्य चेरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट भारतीय विकास बैंक को मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तुत की जानी होती हैं ।

परिवहन राजसहायता योजना : यह योजना देश के पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के संचालन के लिए परिवहन राजसहायता मुहैया करती हैं । यह योजना उत्तर प्रदेश के आठ कथित पहाड़ी जिलों में स्थित इकाइयों पर लागू होती हैं । इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों 50%से 90% तक की दर सीमा में परिवहन राजसहायता का दावा कर सकती ।

3. **एकीकृत अवसरचात्मक विकास योजना :** इस योजना में लघु उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है विशेष रूप से लघु उद्योगों तथा लघु इकाइयों को 5.00 करोड़ रूपये परिव्यय तथा 2.00 करोड़ रू. तक की केन्द्रीय सहायता से अवसरंचना मुहैया कराना है। उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में 3 राज्य आई.डी. केन्द्र गांव उन्नाव (जिला उन्नाव), गांव कोटेवान (जिला मथुरा) तथा यू.पी. एस.आई. डी. क्षेत्र (जिला एटा) स्वीकृत किये गये हैं ।

MoU signed with Harvard Institute of International Dievelopiiieni)

2073. SHRI MUKESH R. PATEL:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Govern-m:nt have signed any MoU with the Harvard Institute of International Development.

(b) if so, the terms and conditions of the agreement;

(c) the details of the aims and objectives of the MoU; and

(d) whether it is a lact that this I'nsti-tute has been blacklisted by US Government earlier and for its dubious activities the US Government has suspended the payme-nt of $ 14 million?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The Foreign Investment Promotion Council (FIP) has entered into an